नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 107
दि. 19.01.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

ईरान में हिंसक प्रदर्शनों का भयावह सच सरकार ने मानी 5 हजार से अधिक मौतें

(जीएनएस)। तेहरान से आई एक चौंकाने वाली आधिकारिक स्वीकारोक्ति ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ईरान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह माना कि देश में हाल के महीनों में चले सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अब तक कम से कम 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में लगभग 500 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। यह पहला मौका है जब खामेनेई नेतृत्व वाली सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। सरकार का दावा है कि इन मौतों के लिए "आतंकवादी तत्व" और हथियारबंद उपद्रवी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने प्रदर्शन की आड़ में हिंसा फैलाई और निर्दोष नागरिकों की हत्या की।

सरकारी बयान के अनुसार सबसे ज्यादा खून-खराबा उत्तर-पश्चिमी ईरान के कुर्द बहुल इलाकों में हुआ, जहां लंबे समय से अलगाववादी समूह सक्रिय रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में प्रदर्शन शांतिपूर्ण न होकर सशस्त्र टकराव में बदल गए, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को इजराइल और विदेशों में सक्रिय कुछ हथियारबंद संगठनों से आर्थिक और सैन्य मदद मिली, जिसने हालात को और भड़का दिया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र

पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है।

दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों से अलग तस्वीर पेश करती हैं। अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन एचआरएएनए के मुताबिक अब तक लगभग 3,308 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4,382 मामलों की जांच अभी भी जारी है। नॉर्वे स्थित हेंगाव संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सबसे क्रूर झड़पें कुर्द इलाकों में हुईं, जहां सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दिनों तक सीधा टकराव चलता रहा। इन प्रदर्शनों के दौरान 24,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र, महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं।

19 दिनों तक चले इन हिंसक प्रदर्शनों ने ईरान की सामाजिक और आर्थिक संरचना को बुरी तरह झकझोर दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 प्रांतों में लगभग 250 मस्जिदें और 20 धार्मिक केंद्र क्षतिग्रस्त हुए। आपातकालीन सेवाओं को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा—182 एम्बुलेंस और अग्निशमन विभाग के उपकरण नष्ट हो गए, जिससे करीब 5.3 मिलियन डॉलर की क्षति हुई। बैंकिंग क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां 317 शाखाएं पूरी तरह तबाह हो गईं और लगभग 4,700 शाखाओं को 10 से 90 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा। 1,400 से ज्यादा एटीएम मशीनें तोड़ी गईं, जिनमें से 250 पूरी तरह बंद हो गईं।

ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र भी इस हिंसा की चपेट से नहीं बच सके। बिजली विभाग को लगभग 6.6 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जिससे कई शहरों में लंबे समय तक बिजली संकट बना रहा। शिक्षा से जुड़े 265 स्कूल, तीन पुस्तकालय, आठ सांस्कृतिक केंद्र और चार सिनेमाघर क्षतिग्रस्त हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नुकसान केवल भौतिक नहीं है, बल्कि ईरानी समाज के मनोवैज्ञानिक ताने-बाने पर भी गहरा असर छोड़ गया है।

ईरान में यह उथल-पुथल ऐसे समय में सामने आई है जब देश पहले से ही आर्थिक प्रतिबंधों, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। सरकार भले ही विदेशी साजिश का आरोप लगा रही हो, लेकिन आम लोगों का गुस्सा वर्षों से जमा सामाजिक-आर्थिक असंतोष का परिणाम माना जा रहा है। हजारों परिवार अपने प्रियजनों की मौत का जवाब मांग रहे हैं, वहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है।

विश्लेषकों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में मौतों की आधिकारिक पुष्टि के बाद ईरान पर वैश्विक दबाव और बढ़ेगा। मानवाधिकार संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। फिलहाल तेहरान की सड़कों पर भले ही सन्नाटा लौट आया हो, लेकिन समाज के भीतर उबल रहा आक्रोश यह संकेत दे रहा है कि यह संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान के इतिहास में यह दौर सबसे रक्तरंजित अध्यायों में से एक के रूप में दर्ज हो चुका है, जिसकी गूंज आने वाले लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी।

मंदिरों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो, मुझे डराने से सच नहीं रुकेगा-संजय सिंह

(जीएनएस)। आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने अपने खिलाफ वाराणसी में दर्ज की गई एफआईआर पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार उन्हें डराने की कोशिश न करे, क्योंकि वह सच बोलने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट और उससे जुड़े ऐतिहासिक मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि मणिकर्णिका घाट हिंदू आस्था का सबसे पवित्र स्थल है, जिसे 18वीं शताब्दी में माता अहिल्याबाई होल्कर ने बनवाया था और बाद में इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया। उसी ऐतिहासिक धरोहर को आज बुरी तरह तोड़ा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मां गंगा मंदिर, प्राचीन शिवालय और अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा तक को क्षति पहुंचाई गई है। यह केवल किसी इमारत को तोड़ने का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सीधा प्रहार है। आप सांसद ने कहा

कि इस कार्रवाई का विरोध सिर्फ उन्होंने नहीं किया, बल्कि काशी के साधु-संतों, स्थानीय पुजारियों, अहिल्याबाई होल्कर के वंशजों और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी आवाज उठाई। इसके बावजूद सरकार ने मंदिरों को तोड़ने वालों पर हाथ डालने के बजाय मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। उन्होंने सवाल किया कि क्या सच बोलना अपराध हो गया है और क्या आस्था की रक्षा के लिए आवाज उठाना गुनाह माना जाएगा। संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मणिकर्णिका घाट मोक्ष की भूमि मानी जाती है, जहां हर दिन हजारों लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। ऐसे पवित्र स्थल के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह बेहद दुखद और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि यह सब किसी मुगल या महमूद गजनवी के दौर में नहीं हो रहा, बल्कि मौजूदा शासन में हो रहा है और वह भी प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र में। स्थानीय लोगों ने मौके से वीडियो बनाए हैं, जिनमें साफ दिखाई देता है कि मंदिरों और घाट के हिस्सों को तोड़ा गया, फिर भी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है।

आप नेता ने कहा कि भाजपा की अब यह नीति बन गई है कि जो भी सरकार से सवाल पूछे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि एफआईआर और मुकदमों से न मैं डरने वाला हूं, न मेरी आवाज दबने वाली है। काशी की आस्था, मंदिरों की सुरक्षा और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का मुद्दा मैं लगातार उठाता रहूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा सवाल किया कि मंदिर तोड़ने वालों पर कार्रवाई कब होगी और दोषियों को बचाने का खेल आखिर क्यों चल रहा है।

संजय सिंह ने कहा कि काशी केवल एक शहर नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा है। यदि यहीं मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश के बाकी हिस्सों का क्या होगा। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त एफआईआर दर्ज हो और क्षतिग्रस्त मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया जाए। आप सांसद ने दो टूक कहा कि सरकार चाहे जितना दबाव बना ले, वह काशी की जनता और संत समाज की आवाज बनकर खड़े रहेंगे और आस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे।

जुर्म साबित होने से पहले जमानत हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार-चंद्रचूड़

(जीएनएस)। जयपुर साहित्य उत्सव के मंच से देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड़ ने न्याय व्यवस्था के एक बेहद संवेदनशील पहलू पर खुलकर अपनी राय रखी और कहा कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध अदालत में साबित नहीं हो जाता, तब तक जमानत उसका मूल अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय संविधान और दंड प्रक्रिया का मूल सिद्धांत "निर्दोष होने का अनुमान" है और इसी भावना के आधार पर न्यायिक व्यवस्था को काम करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार वीर संघवी से बातचीत के दौरान उन्होंने यह टिप्पणी उस सवाल के जवाब में की, जिसमें दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज किए जाने का उल्लेख किया गया था। चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे देश में कई बार ऐसा देखा गया है कि आरोपी वर्षों तक जेल में बंद रहते हैं और अंततः अदालत उन्हें निर्दोष घोषित कर देती है। लेकिन जेल में बीते वे साल कोई वापस नहीं लौटा सकता। उन्होंने इसे न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी त्रासदी बताया। उनके अनुसार जमानत केवल उन्हीं परिस्थितियों में रोकी जानी चाहिए जब यह ठोस आशंका हो कि आरोपी बाहर जाकर फिर अपराध करेगा,

सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या गवाहों को प्रभावित करेगा। इन ठोस आधारों के बिना किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना संविधान की भावना के खिलाफ है।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने यह भी स्वीकार किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में अदालतों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे प्रकरणों में सबूतों की प्रकृति अलग होती है और खतरे का दायरा भी बड़ा होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर आरोपी को अनिश्चित काल तक सलाखों के पीछे रखा जाए। उन्होंने कहा कि जिला और सत्र अदालतों में जमानत अस्वीकार किए जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसके कारण बड़ी संख्या में मामले उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। यह स्थिति बताती है कि जमानत के सिद्धांत को जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू करने की जरूरत है।

न्यायिक सुधारों पर बोलते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या देरी है। मुकदमों का वर्षों तक लंबित रहना न केवल पीड़ित के लिए कष्टदायक होता है, बल्कि आरोपी के मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सुनवाई में अनावश्यक विलंब हो रहा हो तो अदालतों को जमानत देने में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकाल के कुछ ऐतिहासिक फैसलों का भी उल्लेख किया, जिनमें महिलाओं को सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक ठहराना शामिल है।

चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में समाज के प्रतिष्ठित और निष्पक्ष लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, ताकि आम जनता का भरोसा मजबूत हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का लाइव प्रसारण शुरू किया गया, जो संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया। इससे न्यायालय की कार्यप्रणाली आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ हुई है। अपने व्यक्तिगत जीवन पर बात करते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद वे किसी सरकारी पद को स्वीकार नहीं करना चाहते और सामान्य जीवन का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने सामाजिक सुधारों की चर्चा करते हुए वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उनका कहना था कि कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा की रक्षा करना है। जयपुर के इस मंच से दिया गया उनका संदेश स्पष्ट था कि न्याय केवल अदालतों की दीवारों के भीतर सीमित प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता की सबसे मजबूत ढाल है, और जमानत उसी ढाल का पहला सुरक्षा कवच।

इंदौर में टूटा भारतीय सपना, कोहली के शतक के बावजूद न्यूजीलैंड ने रचा नया इतिहास

(जीएनएस)। इंदौर के होलकर स्टेडियम की चमकती शाम भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए मायूसी में बदल गई। जिस मैदान पर अक्सर टीम इंडिया जीत की इबारत लिखती आई है, वहीं इस बार न्यूजीलैंड ने ऐसा अध्याय जोड़ दिया जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तीन मैचों की वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में कीवी टीम ने भारत को 41 रनों से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। यह पहला मौका है जब न्यूजीलैंड ने भारतीय धरती पर वनडे सीरीज जीतने का कारनामा किया। 338 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीदों के ठीक उलट रही। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक जिस धमाकेदार आगाज की आस लगाए थे, वह नदारद दिखा। रोहित शर्मा महज 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान शुभमन गिल से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वे भी 23 रन बनाकर बोल्ड हो गए। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का फ्लॉप शो जारी रहा और स्कोरबोर्ड पर 71 रन ही जुड़े थे कि भारत के चार प्रमुख बल्लेबाज डगआउट में लौट चुके थे। दबाव का पहाड़ इतना ऊंचा हो गया था कि जीत की राह धुंधली नजर आने लगी।

ऐसे मुश्किल समय में एक बार फिर विराट कोहली ने जिम्मेदारी संभाली। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ उन्होंने पारी को संभालने का बीड़ा उठाया। दोनों के बीच 88 रनों की साझेदारी ने मैच में जान फूंक दी। कोहली अपने चिर-परिचित अंदाज में क्रीज पर जमे रहे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजते रहे। नीतीश ने भी उनका भरपूर साथ दिया और 52 गेंदों में अर्धशतक जमाया। लगा कि भारत धीरे-धीरे मुकाबले में वापसी कर रहा है, लेकिन नीतीश के आउट होते ही दबाव फिर बढ़ गया। विराट कोहली ने हार नहीं मानी। हर्षित राणा के साथ उन्होंने एक और महत्वपूर्ण साझेदारी की और 91 गेंदों में अपना 54वां वनडे शतक पूरा किया। स्टेडियम में "कोहली-कोहली" की गूंज सुनाई देने लगी। यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का 85वां शतक था, जो उनकी महानता की एक और मुहर थी। कोहली ने 108 गेंदों पर 124 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। एक समय ऐसा लगा कि किंग कोहली अकेले दम पर भारत को जीत की दहलीज तक ले जाएंगे, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है।

कोहली के आउट होते ही भारतीय पारी बिखर गई। निचले क्रम के बल्लेबाज अपेक्षित योगदान नहीं दे सके और पूरी टीम 46 ओवरों में 296 रनों पर सिमट गई। जीत से महज 41 रन दूर रह जाना भारतीय खेमे के लिए गहरा आघात था। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर ऐतिहासिक उपलब्धि की चमक साफ दिखाई दे रही थी।

कीवी गेंदबाजों ने अनुशासन और रणनीति का शानदार नमूना पेश किया। क्रिस्टियन क्लार्क और जकारी फाउलकेस ने तीन-तीन विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उन्होंने सही लेंथ, सटीक लाइन और धीमी गेंदों का बेहतरीन मिश्रण इस्तेमाल किया, जिससे भारतीय बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं सके। न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी बेहद चुस्त रही, जिसने कई महत्वपूर्ण रन बचाए।

सीरीज का सफर भी उतार-चढ़ाव भरा रहा। वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में भारत ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर शानदार शुरुआत की थी। राजकोट में न्यूजीलैंड ने वापसी करते हुए 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया और सीरीज बराबरी पर ला दी। इंदौर का यह तीसरा मैच निर्णायक साबित हुआ, जहां कीवी टीम ने संयम और साहस का परिचय देते हुए इतिहास रच दिया।

यह हार भारतीय टीम के लिए कई सवाल छोड़ गई है। मध्यक्रम की नाकामी, शुरुआती विकेटों का जल्दी गिरना और गेंदबाजी में आखिरी ओवरों की कमजोरी फिर उजागर हुई। विराट कोहली की शतकीय पारी जरूर उम्मीद जगाती है, लेकिन क्रिकेट टीम गेम है और एक खिलाड़ी के भरोसे हर बार नैया पार नहीं लग सकती। दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने दिखा दिया कि योजनाबद्ध क्रिकेट कैसे खेला जाता है।

श्रीलंका की धरती पर भारतीय पर्यटकों का जलवा, पर्यटन में फिर बना नंबर-1 देश

(जीएनएस)। हिंद महासागर की गोद में बसे श्रीलंका के लिए वर्ष 2025 पर्यटन के लिहाज से ऐतिहासिक साबित हुआ है। आर्थिक संकट के बाद जिस तेजी से इस द्वीपीय देश ने खुद को संभाला, उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत से आने वाले पर्यटकों का रहा। श्रीलंका टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पूरे साल में लगभग 23 लाख विदेशी सैलानी श्रीलंका पहुंचे, जिनमें सबसे बड़ी संख्या भारत से आने वालों की रही। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रिश्तों की गहरी जड़ों का प्रमाण है।

रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कुल 5,31,511 भारतीय पर्यटकों ने श्रीलंका की यात्रा की, जो किसी भी दूसरे देश से आने वाले यात्रियों की संख्या से दोगुने से भी अधिक है। पिछले कई वर्षों से भारत श्रीलंका के पर्यटन उद्योग की रीढ़ बना हुआ है और इस बार भी यह सिलसिला और मजबूत हुआ। भारतीय परिवारों, हनीमून कपल्स, तीर्थयात्रियों और एडवेंचर पसंद युवाओं के लिए श्रीलंका सबसे पसंदीदा विदेशी गंतव्य के रूप में उभरा है। कोलंबो की चमचमाती सड़कों से लेकर कैंडी के प्राचीन मंदिरों और गॉल के समुद्री किलों तक हर जगह भारतीय पर्यटकों की चहल-पहल नजर आई।

खास बात यह रही कि 2024 की तुलना में 2025 में भारतीय पर्यटकों की संख्या में करीब 1.14 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो लगभग 15 प्रतिशत का इजाफा है। औसतन हर महीने आने वाले विदेशी पर्यटकों में 23 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी अकेले भारत की रही। श्रीलंका के पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि सस्ती हवाई सेवाएं, वीजा प्रक्रिया में सरलता और भारतीय संस्कृति से मिलती-जुलती जीवनशैली इस आकर्षण के प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा रामायण सर्किट, बौद्ध तीर्थ स्थल और समुद्री पर्यटन ने भी भारतीयों को खूब लुभाया।

साल का सबसे व्यस्त महीना दिसंबर रहा, जब 56,715 भारतीय पर्यटक श्रीलंका पहुंचे। नए साल की छुट्टियों, शादी के मौसम और सुहावने मौसम के कारण यह महीना पर्यटन उद्योग के लिए वरदान साबित हुआ। इसके विपरीत फरवरी में भारतीय पर्यटकों की संख्या सबसे कम, लगभग 35 हजार रही, लेकिन इसके बावजूद भारत पहले स्थान पर बना रहा। दिसंबर में कुल विदेशी आगंतुकों की संख्या 2,58,928 दर्ज की गई, जो यह साबित करती है कि श्रीलंका अब फिर से वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से लौट आया है।

देशवार आंकड़ों में भारत के बाद ब्रिटेन दूसरे स्थान पर रहा, जबकि रूस, जर्मनी और फ्रांस भी प्रमुख स्रोत देशों में शामिल रहे। कुल विदेशी पर्यटकों में से 92.7 प्रतिशत यूरोप और एशिया–पैसिफिक क्षेत्र से आए, जिनमें अकेले यूरोप की हिस्सेदारी 51.3 प्रतिशत रही। श्रीलंका सरकार का कहना है कि समुद्री तटों की साफ-सफाई, नई होटल परियोजनाओं और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था ने विदेशी यात्रियों का भरोसा बढ़ाया है। दिलचस्प बात यह है कि 2026 की शुरुआत भी श्रीलंका के लिए बेहद उत्साहजनक रही। जनवरी के पहले पंद्रह दिनों में ही 1,31,898 पर्यटक वहां पहुंच गए, जो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है। 15 जनवरी को एक ही दिन में रिकॉर्ड 10,483 विदेशी सैलानियों का आगमन हुआ। इस अवधि में भी सबसे ज्यादा 23,786 पर्यटक भारत से आए, जबकि रूस, ब्रिटेन और जर्मनी क्रमशः अगले स्थानों पर रहे। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री का मानना है कि भारत और श्रीलंका के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने, रुपया–रुपये में लेनदेन की सुविधा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने से यह आंकड़ा आने वाले वर्षों में और ऊपर जाएगा। भारतीय यात्रियों के लिए श्रीलंका केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि घर जैसा अनुभव देने वाला पड़ोसी देश बन चुका है। यही कारण है कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सहारा देने में भारतीय पर्यटकों की भूमिका सबसे अहम साबित हो रही है और आने वाले समय में यह साझेदारी और गहरी होती नजर आ रही है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

बीएमसी के नतीजे बड़े बदलाव के संकेत

एकनाथ शिंदे ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव में जीते अपने पार्षदों को जिस तरह एक होटल में भेज दिया, वह कदम न केवल असामान्य दिखता है बल्कि इसके पीछे की मंशा को समझना भी चुनौतीपूर्ण है। सवाल उठता है कि आखिर एकनाथ शिंदे के पार्षदों को किससे खतरा है? क्या उनके टूटने की आशंका है या फिर भाजपा के मेयर को समर्थन देने के लिए कोई कीमत वसूलने की योजना है? कारण जो भी हों, यह स्पष्ट है कि भाजपा और शिंदे शिवसेना के बीच संबंधों में खटपट लगातार बनी रहती है।

विधानसभा चुनावों के बाद भी दोनों दलों के बीच खींचतान की झलक मिलती रही। विभागों के बंटवारे को लेकर मतभेद सामने आए और नीतिगत समझौतों में टकराव दिखाई दिया। शिंदे शिवसेना का तर्क है कि उनके पार्षदों को पार्षद के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए होटल में एकत्र किया गया, लेकिन यह तर्क संतोषजनक नहीं लगता। इसके कारण विपक्षी दलों को कटाक्ष करने का अवसर मिल गया, जो शिंदे शिवसेना ने स्वयं ही उपलब्ध करा दिया। यह समझना भी कठिन है कि जब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना राज्य में सत्ता में साझेदार है और बीएमसी समेत अन्य निकाय चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ी थी, तब अपने पार्षदों को होटल में क्यों बुलाया गया। इस कदम से यह संदेश जाता है कि दोनों दलों के बीच अविश्वास अभी भी जड़ें जमाए हुए हैं। संभावना है कि शिंदे शिवसेना के पार्षदों ने होटल में ठहराव इसलिए रखा ताकि वे बीएमसी में महत्वपूण पद या अन्य लाभ सुनिश्चित कर सकें। यह स्थिति बीएमसी की शानदार जीत के बावजूद दलों के बीच अविश्वास को उजागर करती है और नगर प्रशासन की क्षमता पर भी सवाल खड़ा करती है। राजनीतिक दल नगर निकायों में जीत तो हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास करते हैं, लेकिन नगरों की दशा-दिशा सुधारने के लिए ईमानदारी से काम करना कम ही देखते हैं। इसी रवैये के कारण देश के छोटे-बड़े शहर विकास की अपेक्षा से पीछे रह जाते हैं। मुंबई जैसे महानगर, जो अपनी प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति के लिए पूरे देश में उदाहरण होना चाहिए, वहां शहर की वास्तविकताओं के सुधार में लगातार विफलता देखने को मिल रही है। नतीजतन, शहरी जीवन कष्टप्रद बनता जा रहा है। गंदगी, प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और बढ़ती झुग्गी-बस्तियों जैसी समस्याएं आम हो रही हैं।

बीएमसी देश का सबसे धनी नगर निकाय है। उसका वार्षिक बजट कई राज्यों के बजट से भी अधिक है। इसके बावजूद नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ रही है। यदि बीएमसी के मेयर का चयन सुगमता से नहीं होता, तो मुंबई जैसी आर्थिक राजधानी का विकास और सुचारू प्रशासन संभव नहीं हो पाता। होटल में पार्षदों का डेरा सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि मुंबई जैसे महानगर की शासन प्रणाली और नागरिक कल्याण के मुद्दे पर भी प्रकाश डालता है। यह दर्शाता है कि राजनीति में व्यक्तिगत हित और दलगत रणनीति कभी-कभी सार्वजनिक कल्याण से ऊपर उठ जाती है। शहर के नागरिकों की अपेक्षाएं और उनके अधिकार, प्रशासनिक और राजनीतिक समझौतों की जटिलताओं में खो जाते हैं। इस घटनाक्रम से यह भी संकेत मिलता है कि नगर निकायों में सत्ता साझा करने वाले दलों के बीच पारदर्शिता और विश्वास की कमी कितनी गहरी है। जबकि बीएमसी में जीत दलों की राजनीतिक क्षमता का परिचायक हो सकती है, लेकिन पार्षदों का होटल में समेटना और पदों के लिए संभावित सौदेबाजी का माहौल सार्वजनिक हित और प्रशासनिक सुधारों को गंभीर चुनौती देता है। मुंबई की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल नगर निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों को केवल सत्ता के साधन के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें नागरिक कल्याण और नगर सुधार के जिम्मेदार भी मानें। पार्षदों के प्रशिक्षण और एकत्रीकरण के उद्देश्य यदि प्रशासनिक दक्षता और सेवा सुधार से जुड़े होते, तो नागरिकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में, यह कदम राजनीतिक खेल और दलगत रणनीति के रूप में ज्यादा दिखाई देता है। बीएमसी की संपन्नता और बजट की उपलब्धता के बावजूद यदि शहर के नागरिक बुनियादी सुविधाओं, साफ-सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सत्ता का उपयोग अधिकतर दलगत लाभ और रणनीति के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार, होटल में पार्षदों का एकत्र होना केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह शहर की राजनीति, नगर प्रशासन और नागरिक जीवन की अस्थिरताओं का प्रतीक बन गया है। मुंबई जैसे महानगर को सुचारू प्रशासन, पारदर्शिता और भरोसे के साथ चलाना तभी संभव है, जब राजनीतिक दल जीत के बाद अपने प्रतिनिधियों को केवल पदों और लाभ के लिए नहीं, बल्कि नगर सुधार और नागरिक सुविधा के लिए सक्रिय रूप से तैयार करें।

सीनियर और युवा नेताओं के बीच संतुलन स्थापित करना नितिन नबीन के लिए होगी बड़ी चुनौती

> “ हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नबीन के पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने के साथ ही पार्टी में नए और बड़े बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। नितिन नबीन बीजेपी के न केवल सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे बल्कि वह पार्टी के पहले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जिनका जन्म पार्टी की स्थापना के बाद हुआ है।

भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख जारी हो गई है। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी बनाए गए डॉ के.लक्ष्मण ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। संगठन पर्व - 2024 के तहत जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, पार्टी ने शुक्रवार को ही निर्वाचक मंडल सूची का प्रकाशन कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू हो जाएगी। 19 जनवरी को ही दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। इसी दिन शाम को 4 से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। शाम 5 से 6 बजे तक नाम वापस लिया जा सकता है। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए एक से अधिक नेता नामांकन भरेंगे तो 20 जनवरी को चुनाव करवाया जाएगा। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए बीजेपी में कभी भी चुनाव की नौबत नहीं आई है। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि 20 जनवरी को सर्वसम्मति से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के चुने जाने का ऐलान कर दिया जाएगा।

हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नबीन के पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने के साथ ही पार्टी में नए और बड़े बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। नितिन नबीन बीजेपी के न केवल सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे बल्कि वह पार्टी के पहले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जिनका जन्म पार्टी की स्थापना के बाद हुआ है। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी जबकि नितिन नबीन का जन्म

इसके 47 दिन बाद 23 मई 1980 को हुआ था। ऐसे में अब बीजेपी आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह साबित करने की भी है कि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी सिर्फ प्रतीकात्मक बदलाव का पर्याय भर बन कर न रह जाए। वहीं नई बीजेपी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका दिया जाना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बिहार से आने वाले इन युवा नेता के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी टीम का गठन करना होगा। पार्टी संविधान के मुताबिक, पार्टी में सर्वोच्च फैसला लेने वाली इकाई पार्टी का संसदीय बोर्ड है। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति का नंबर आता है जो चुनाव के समय उम्मीदवारों का चयन करता है। फिलहाल संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जेपी नड्डा है लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद नितिन नबीन ही पार्टी का फैसला लेने वाले इस सर्वोच्च इकाई के अध्यक्ष होंगे। वर्तमान में नड्डा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बी एस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के.लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव और सत्यनारायण जटिया संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष संसदीय बोर्ड के सचिव के तौर पर इसमें शामिल हैं। इनमें से बीएल संतोष को छोड़कर बाकी सभी नेता 60 से ज्यादा उम्र के हैं। संसदीय बोर्ड के ये सारे सदस्य पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के भी सदस्य हैं। संसदीय बोर्ड में शामिल इन 11 नेताओं के अलावा भूपेन्द्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, और वनथी श्रीनिवासन केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल हैं। सरकार के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नबीन की अध्यक्षता वाले पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति दोनों में ही शामिल रहेंगे। वहीं सरकार और पार्टी के अहम नेता के तौर पर अमित शाह भी इन दोनों समितियों का हिस्सा रहेंगे। लेकिन युवा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने के लक्ष्य और नई बीजेपी के गठन के लिए कई दिग्गज नेताओं को इससे बाहर जाना ही पड़ेगा। इन दोनों समितियों का पुनर्गठन करने के बाद पार्टी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन को अपनी राष्ट्रीय टीम - यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्षों, राष्ट्रीय महासचिवों, राष्ट्रीय सचिवों और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के साथ-साथ विभिन्न मोर्चों , समितियों और विभागों के मुखियाओं की भी नियुक्ति करनी पड़ेगी। यह बात तो साफ है कि ये सारे फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सहमति से ही लिए जाएंगे। हालांकि राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे नेताओं के बारे में अंतिम फैसला करने से पहले संघ से भी चर्चा की जाएगी। पार्टी की राष्ट्रीय टीम में ऐसे कई अन्य नेता भी शामिल हैं जो अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं और इसलिए उन्हें हटाने से पहले कई समीकरणों का ध्यान भी रखना पड़ेगा।

ऐसे में यह देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि नितिन नबीन इन तमाम चुनौतियों से निपटते हुए अपनी नई टीम कैसे तैयार कर पाते हैं और कैसे तमाम उम्र के नेताओं यानी सीनियर एवं युवा के बीच संतुलन बना पाने में कामयाब हो पाते हैं।

प्रेरणा

मधुर गीतों की कोमल वापसी: शोर से परे दिल की सुनहरी दुनिया

दिल को छू लेने वाले गीत किसी मौसम की तरह होते हैं—धीरे-धीरे उतरते हैं, भीतर जगह बनाते हैं और फिर लंबे समय तक मन के आकाश में ठहरे रहते हैं। आज जब चारों तरफ तेज़ बीट्स, ऊंची आवाज़ और तात्कालिक रोमांच से भरा संगीत सुनाई देता है, तब अनायास उन पुराने मधुर गीतों की याद आती है जो बिना शोर किए सीधे आत्मा से संवाद कर लेते थे। वे गीत केवल मनोरंजन नहीं थे, एक अनुभव थे, एक निजी बातचीत की तरह, जिनमें इंसान अपने सुख-दुख, प्रेम-विरह और अकेलेपन की परछाइयां देख लेता था। आज ऐसे गीत हाशिये पर क्यों चले गए, यह केवल संगीत का प्रश्न नहीं, हमारे समय और जीवनशैली का भी प्रश्न है। किसी गीत का दिल तक पहुंचना महज धुन की मिठास से तय नहीं होता। उसमें शब्दों की सादगी, स्वर का ठहराव और भावना की सच्चाई का अदृश्य मेल काम करता है। पुराने दौर के गीतकार और संगीतकार इस रहस्य को गहराई से समझते थे। इसलिए वे सुरों को केवल कानों के लिए नहीं, मन के लिए गढ़ते थे। नीचे सुरों में रची धुनें मानो श्रोता का हाथ पकड़कर भीतर की गलियों में ले जाती थीं। लता मंगेशकर का गाया “लग जा गले” सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत अपना धीरे से पुकार रहा हो। किशोर कुमार का “चिंगारी कोई भड़के” दर्द को चीख में नहीं, मौन में बदल देता है। रफी और लता का “अभी न जाओ छोड़कर” प्रेम का ऐसा सभ्य आग्रह है जिसमें शोर की कोई जगह नहीं। इन गीतों की ताकत उनकी धीमी चाल में छिपी थी। भारतीय संगीत परंपरा में मंद्र और मध्य सप्तक को गंभीरता और आत्मसंवाद का क्षेत्र माना गया है। नीचे सुरों में गाना आसान नहीं होता; उसमें सांसों का संतुलन, उच्चारण की सफाई और भाव की पकड़ चाहिए। पुराने गायक वर्षों की रियाज़ से इस कला को साधते थे। वे किरदार की मनःस्थिति को समझकर गाते थे, इसलिए आवाज़ परदे के चेहरे से अलग नहीं लगती थी। आज तकनीक ने गायकी को आसान तो बना दिया है, पर आत्मा से थोड़ा दूर भी कर दिया है। ऑटो-ट्यून और डिजिटल इफेक्ट्स से सुर चमक जाते हैं, मगर भीतर की कसक अक्सर खो जाती है। समय के बदलने के साथ संगीत सुनने का तरीका भी बदल गया। कभी गीत रेडियो पर इत्मीनान से सुने जाते थे, कैसेट और रिकॉर्ड प्लेयर पर दोहराए जाते थे। आज संगीत मोबाइल की छोटी स्क्रीन और छोटे स्पीकरों में सिमट गया है। रील्स के लिए बने तीस सेकंड के टुकड़ों में गहराई वाले सुरों की गुंजाइश कम रह जाती है। निर्माता भी वही बनाते हैं जो तुरंत ध्यान खींच सके। तेज़ बीट्स और ऊंचे सुर पहले ही पल में असर डाल देते हैं, जबकि मधुर गीत धीरे-धीरे खुलते हैं, जैसे कोई किताब धैर्य मांगती है। बाजार की इस हड़बड़ी ने ठहराव वाले संगीत को जोखिम भरा मान लिया है।

फिर भी यह कहना गलत होगा कि मधुर गीत पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। वे आज भी कहीं-कहीं सांस ले रहे हैं। “अगर तुम साथ हो” सुनते हुए लगता है जैसे पुराने दौर की गंभीरता आधुनिक संवेदना से हाथ मिला रही हो। “फिर ले आया दिल” या “इकतारा” जैसे गीत बताते हैं कि आज भी ऐसी रचनात्मकता संभव है जो शोर से नहीं, अनुभूति से बात करे। अरिजीत सिंह की आवाज़ में कई बार वह ठहराव लौट आता है जिसकी हमें तलाश रहती है। लेकिन ये गीत अपवाद की तरह सामने आते हैं, मुख्यधारा की धारा अब दूसरी दिशा में बह रही है।

समस्या केवल संगीतकारों की नहीं, हमारी सामूहिक सुनने की आदतों की भी है। हम जल्दी में हैं—रास्ते में, दफ्तर में, सोशल मीडिया की भीड़ में। जहां ध्यान ही ठहरा हुआ न हो, वहां ठहरे हुए सुर कैसे टिकें। नीचे सुर का गीत एकांत चाहता है, थोड़ा समय चाहता है, जैसे कोई दोस्त दिल की बात करने से पहले माहौल बनाता है। आज का श्रोता अक्सर उतना धैर्य नहीं दे पाता। इसलिए कंपनियां भी ऐसे गीतों में कम निवेश करती हैं। निर्णय लेने वाले लोग आंकड़ों से चलते हैं और आंकड़े तेज़, चमकीले और वायरल संगीत के पक्ष में खड़े दिखते हैं।

इसके बावजूद दिल की जरूरतें बदली नहीं हैं। इंसान आज भी उदास होता है, प्रेम में डूबता है, अकेलेपन से जूझता है। इन भावों को व्यक्त करने के लिए शोर नहीं, सुकून चाहिए। यही कारण है कि जब भी कोई सच्चा मधुर गीत आता है, वह तुरंत अपनी जगह बना लेता है। शादियों के शोर के बीच भी लोग देर रात पुराने गाने लगाकर चुपचाप सुनना चाहते हैं। टैक्सी के रेडियो पर अचानक “वो शाम कुछ अजीब थी” बज उठे तो समय जैसे धीमा पड़ जाता है। इसका मतलब है कि भीतर कहीं वह संवेदनशील श्रोता अब भी जीवित है।

फिल्म संगीत कभी केवल पृष्ठभूमि का शोर नहीं था, वह कहानी का अदृश्य पात्र होता था। गीत नायक-नायिका की जगह बोलते थे, उनके मन की परतें खोलते थे। आज दृश्य अधिक बोलने लगे हैं, गीत की भूमिका छोटी हो गई है। कई बार कलाकार खुद गायक बन जाते हैं, इसलिए भाव से ज्यादा छवि हावी हो जाती है। प्रशिक्षण की जगह प्रस्तुति का दबाव बढ़ गया है। नीचे सुर में गाने के लिए जिस अनुशासन की जरूरत होती है, वह तेजी से घट रहा है। पर यह स्थिति स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि कला अंततः इंसान की भीतरी मांग से चलती है।

हो सकता है आने वाले वर्षों में संगीत फिर एक मोड़ ले। जब लोग शोर से ऊबेंगे, तब वे दोबारा ठहराव खोजेंगे। जैसे फैशन में पुराने रंग लौट आते हैं, वैसे ही सुरों का स्वभाव भी लौटता है। स्वतंत्र संगीत का बढ़ता संसार इस उम्मीद को मजबूत करता है। इंटरनेट ने भले ही तात्कालिकता बढ़ाई हो, पर उसी ने अलग-अलग तरह के संगीत को जगह भी दी है। बहुत से युवा कलाकार आज पारंपरिक रागों और मंद्र सप्तक के प्रयोग कर रहे हैं, भले ही मुख्यधारा उन्हें तुरंत स्वीकार न करे।

असल सवाल यह नहीं कि मधुर गीत कब लौटेंगे, बल्कि यह है कि क्या हम उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं। गीत और श्रोता का रिश्ता दोतरफा होता है। यदि हम थोड़ा समय, थोड़ा एकांत और थोड़ा धैर्य दें, तो संगीतकार भी वही भाषा बोलेंगे। दिल तक उतरने वाला गीत किसी आदेश से पैदा नहीं होता, वह समाज के भीतर की संवेदनशीलता से जन्म लेता है। इसलिए उम्मीद छोड़ी नहीं जा सकती।

आईएनडीआईए की परीक्षा का साल राष्ट्रीय राजनीति पर होगा दूरगामी असर

नए साल के शुरू में ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रार और उसमें संवैधानिक प्रविधानों-परंपराओं को ताक पर रख देना बता रहा है कि साल 2026 भारतीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। इस साल चार राज्यों-बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल तथा केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से तीन में आईएनडीआईए के घटक दलों की सरकारें हैं, जबकि दो में भाजपानीत राजग की।

इन राज्यों की सत्ता में होने वाला बदलाव राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर भी असर डालेगा, क्योंकि विधानसभाओं के गणित से संसद के उच्च सदन राज्यसभा में संख्या बल प्रभावित होगा। इसी साल राज्यसभा की 75 सीटों के लिए भी चुनाव होने हैं। साल की शुरुआत देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई यानी बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निकाय चुनावों से हुई है। बीएमसी चुनाव में भाजपा को पहली बार जीत मिली है और ठाकरे बंधुओं-उद्धव और राज को साथ आने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा है। महत्वपूर्ण तो हर राज्य की सत्ता होती है, पर देश की निगाहें फिलहाल पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। ग्यारह साल से केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और डेढ़ दशक से बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक कटुता चरम पर है। घुसपैठ, एसआईआर और भ्रष्टाचार पर तो तकरार बरकरार है ही, आई-पैक के चेयरमैन के दफ्तर पर ईडी के छापे और उसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वहां पहुंच कर कुछ दस्तावेज ले जाने के बाद बंगाल की सत्ता का संघर्ष चुनाव से पहले ही सड़कों पर नजर आ रहा है।

ममता इसे केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर ईडी का डाका बता रही हैं तो केंद्र सरकार और भाजपा इसे सरकारी एजेंसी के कामकाज में एक मुख्यमंत्री द्वारा अवरोध डालने का अभूतपूर्व मामला बता रहे हैं। कांग्रेस और वाम मोर्चा अब बंगाल की राजनीति में हाशिये पर हैं। सत्ता की लड़ाई तृणमूल और भाजपा के बीच है। पिछले चुनाव में खुद ममता को हरा कर भाजपा सनसनी फैलाने में तो सफल रही, लेकिन 294 सदस्यीय विधानसभा में 77 सीटों तक ही पहुंच पाई। तृणमूल 215 सीटें जीत गई। तृणमूल को 48 और भाजपा को 38 प्रतिशत मत मिले थे।

2024 के लोकसभा चुनाव में यह फासला बढ़ गया। यही फासला तय करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। तीन कार्यकाल के बाद सत्ता विरोधी भावना स्वाभाविक है, पर ममता के ‘बांग्ला अस्मिता’ के मुद्दे की काट भाजपा नहीं कर पा रही। एसआईआर और घुसपैठिया विवाद के बीच अगर भाजपा बंगाल में महाराष्ट्र और बिहार की पुनरावृत्ति कर पाई तो उसका राष्ट्रीय राजनीति पर भी दूरगामी असर होगा।

दूसरा बड़ा और मुश्किल राज्य तमिलनाडु है। वहां द्रमुक की सरकार है, जो ‘इंडिया’ का घटक दल है। दशकों से तमिल राजनीति द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच बंटी रही, लेकिन जयललिता के निधन के बाद परिदृश्य बदला है। अन्नाद्रमुक और अभिनेता विजय के इर्दगिर्द भाजपा चुनावी बिसात बिछाना चाहती है, पर किसी चमत्कार की खुशफहमी उसे भी नहीं है। उत्तर भारत में भाजपा की लहर चलाने वाले मुद्दे दक्षिण में अभी तक तो नहीं चले हैं। एमके स्टालिन सरकार के विरुद्ध सत्ता विरोधी भावना के अलावा वंशवाद, भ्रष्टाचार और हिंदी विरोध सरीखे मुद्दे भी हैं, पर उनका चुनावी लाभ उठाने के लिए विश्वसनीय विकल्प भी चाहिए। भाजपा की रणनीति फिलहाल गठबंधन के जरिये मत प्रतिशत बढ़ाने की ज्यादा लगती है।

पिछले लोकसभा चुनाव में अभिनेता सुरेश गोपी के सांसद बनने और हाल में तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर बनाने के करिश्मे के बावजूद भाजपा केरल में हाशिये पर ही है। केरल में सत्ता राजनीति वाम मोर्चा ‘एलडीएफ’ और कांग्रेसी मोर्चा ‘यूडीएफ’ के बीच बंटी है। हालांकि हर चुनाव में सरकार बदल जाने का सिलसिला पिछली बार वामपंथी मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने तोड़ दिया। इस बार उनके विरुद्ध ज्यादा सत्ता विरोधी भावना की उम्मीद है, पर उसका चुनावी लाभ कांग्रेस को ही मिल सकता है। अपने अंतिम दुर्ग की सत्ता से विदाई वाम राजनीति के लिए बड़ा झटका साबित होगी। वहीं असम पूर्वोत्तर भारत की राजनीति का प्रवेश द्वार माना जाता है।

वहां की सत्ता कब्जाने के बाद ही भाजपा का पूर्वोत्तर में विस्तार हुआ, जिसका श्रेय पूर्व कांग्रेसी हिमंता बिस्वा सरमा को जाता है। बंगाल की तरह असम में भी घुसपैठ बड़ा चुनावी मुद्दा है, जिस पर आक्रामकता के साथ कांग्रेस को भाजपा घेरती रही है। कांग्रेस की सारी उम्मीदें वहां गौरव गोगोई के नेतृत्व तथा क्षेत्रीय दलों से तालमेल पर टिकी हैं। पुदुचेरी की राजनीति अक्सर तमिलनाडु की राह चलती रही है, लेकिन 2021 से वहां भाजपा समर्थित एन रंगासामी सरकार है।

30 सदस्यीय पुदुचेरी विधानसभा में 10 सीटें जीतने वाली ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने छह सीटें जीतने वाली भाजपा के साथ मिल कर सरकार बनाई। अगर कांग्रेस और द्रमुक सत्ताविरोधी भावना का लाभ उठाते हुए आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो भाजपा को दक्षिण भारत में अपना एकमात्र शेष सत्ता दुर्ग भी गंवाना पड़ सकता है। ये विधानसभा चुनाव परिणाम भाजपा की भावी चुनावी तैयारियों पर भी असर डालेंगे, लेकिन आईएनडीआईए का तो भविष्य ही एकता और सफलता पर निर्भर करेगा, क्योंकि चुनाव-दर-चुनाव उसमें दरारें बढ़ती जा रही हैं।

अभियान

गुप्त नवरात्र में घटस्थापना और मंत्रों का जप, घर और जीवन में खुशियों की बरसात

भारतीय संस्कृति में नवरात्र का पर्व अत्यंत महत्व रखता है। यह केवल नौ दिनों तक चलने वाला उत्सव नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति, सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक बल लाने का माध्यम भी है। खासकर गुप्त नवरात्र, जो माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाया जाता है, साधकों के लिए अत्यधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। इस वर्ष गुप्त नवरात्र 19 जनवरी से 27 जनवरी 2026 तक मनाया जाएगा। गुप्त नवरात्र का यह पर्व सामान्य नवरात्र से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें दस महाविद्याओं की उपासना की जाती है और इसे विशेष रूप से मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित किया जाता है।

घटस्थापना नवरात्र की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन घर में देवी शक्ति का आवाहन करने के लिए मिट्टी या तांबे के पात्र में जल, हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल, इत्र और विशेष प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाता है। घटस्थापना केवल घर में एक पवित्र पात्र रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और देवी शक्ति को आमंत्रित करने का माध्यम है। घटस्थापना के समय साधक का हृदय श्रद्धा और भक्ति से भरा होना चाहिए। यह दिन मानसिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है।

गुप्त नवरात्र में दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ये देवी रूप शक्ति, संकल्प, साहस, समृद्धि, मानसिक स्थिरता और आंतरिक संतुलन का प्रतीक हैं। साधक यदि पूरे श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ इन देवी रूपों की पूजा करता है और मंत्रों का जप करता है, तो उसके जीवन में सुख-शांति, समृद्धि और मानसिक स्थिरता आती है। विशेष रूप से गुप्त नवरात्र में देवी मां दुर्गा और उनके नौ रूपों की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह पर्व घर और परिवार में सुख, प्रेम, सौहार्द्र और आंतरिक संतुलन स्थापित करने का माध्यम भी बनता है।

घटस्थापना के समय मंत्रों का जप अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मंत्रों की शक्ति साधक के मन, शरीर और वातावरण को दिव्यता से भर देती है। सबसे पहला और प्रभावशाली मंत्र है ‘ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे’। इसे दस महाविद्याओं में से शक्ति का संपूर्ण प्रतिनिधित्व माना गया है। साधक यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप करता है, तो उसे मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। इस मंत्र का उच्चारण घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है।

इसके अलावा ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’ मंत्र का जप करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यह मंत्र साधक के जीवन में सुरक्षा और मानसिक स्थिरता लाता है। गुप्त नवरात्र में इसका जप करने से साधक को भय, संकट और नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलती है। यह मंत्र घर और परिवार में प्रेम, सहयोग और एकता बनाए रखने में सहायक होता है। साथ ही यह मंत्र साधक के आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाता है।

गुप्त नवरात्र में ‘ॐ क्लीं कालिकायै नमः’ मंत्र का जप करना भी अत्यंत लाभकारी है। देवी काली शक्ति, साहस और संकल्प की प्रतीक हैं। यह मंत्र कठिन परिस्थितियों में साहस, विवेक और धैर्य प्रदान करता है। घर में इस मंत्र का जप करने से परिवार में एकता, प्रेम और सुख-शांति बनी रहती है। यह मंत्र मानसिक स्थिरता और सकारात्मक सोच को भी विकसित करता है।

साधक अपने ध्यान और श्रद्धा के साथ ‘ॐ ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः’ मंत्र का जप कर सकता है। देवी लक्ष्मी धन, समृद्धि और खुशहाली की प्रतीक हैं। गुप्त नवरात्र में इसका जप करने से घर में आर्थिक स्थिरता, व्यापार और नौकरी में सफलता और जीवन में समृद्धि आती है। विशेषकर उन परिवारों के लिए यह मंत्र अत्यंत लाभकारी है, जिनके घर में धन-संपत्ति और सुख-शांति की कमी अनुभव होती है।

गुप्त नवरात्र में प्रत्येक दिन एक देवी रूप की विशेष पूजा और मंत्र जप करना आवश्यक है। दस महाविद्याओं के प्रत्येक रूप को ध्यान और श्रद्धा के साथ साधक पूजता है। प्रतिदिन की पूजा के दौरान फूल, दीप, अगरबत्ती, फल और नैवेद्य अर्पित करना लाभकारी माना गया है। विधिपूर्वक पूजा और मंत्र जप करने से न केवल देवी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि परिवार में प्रेम, सहयोग और सद्भाव भी बढ़ता है।

साधक को गुप्त नवरात्र के दौरान सात्विक आहार, संयम और मानसिक शांति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस अवधि में सात्विक भोजन का सेवन, ब्रह्मचर्य का पालन और सकारात्मक सोच का अभ्यास आवश्यक है। प्रतिदिन प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। यह साधक की आंतरिक ऊर्जा को शुद्ध करता है और मंत्रों की शक्ति को बढ़ाता है।

अत्यंत शुभ मुहूर्त पर घटस्थापना करने से मंत्रों का प्रभाव और भी गहरा होता है। इस वर्ष 2026 में घटस्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 07:12 बजे से 09:45 बजे तक है। इस समय स्थापित घट में जल, पुष्प, हल्दी, कुमकुम और बीज डालकर देवी शक्ति का आवाहन किया जाता है। घटस्थापना के बाद प्रतिदिन जल को बदलना और उसमें ताजे पुष्प डालना अनिवार्य है। यह पूजा के प्रभाव को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है।

गुप्त नवरात्र के दौरान मंत्रों का जप लगातार और नियमित रूप से करना चाहिए। ‘ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे’, ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’, ‘ॐ क्लीं कालिकायै नमः’, और ‘ॐ ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः’ मंत्रों का जप श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से साधक के जीवन में सुख-शांति, समृद्धि और मानसिक स्थिरता आती है। यह मंत्र घर और परिवार को नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं।

गुप्त नवरात्र के दौरान साधक को अपने हृदय में पूर्ण भक्ति और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। मंत्रों का जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह साधक के हृदय और मस्तिष्क में देवी शक्ति का संचार करता है। इसका परिणाम केवल सांसारिक लाभ ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होता है। साधक इस दौरान अपने आंतरिक बल, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है।

गुप्त नवरात्र के दौरान साधक को दस महाविद्याओं की पूजा करते समय प्रत्येक देवी के महत्व, गुण और शक्ति को समझना चाहिए। इससे साधक का ध्यान केंद्रित रहता है और पूजा का प्रभाव अधिक गहरा होता है। प्रत्येक देवी का मंत्र जप करने से साधक के जीवन में उस देवी की विशेष शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल प्रदान करती है।

गुप्त नवरात्र की समाप्ति नवमी तिथि को होती है। नवमी के दिन विशेष रूप से देवी महाविद्या की पूजा और आरती करना शुभ माना गया है। इस दिन दीप प्रज्वलन, मंत्र जप और देवी को प्रसाद अर्पित करना अत्यंत लाभकारी है। नवमी के दिन की पूजा से साधक को देवी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और घर और परिवार में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है।

गुप्त नवरात्र के दौरान साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजा का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है। मंत्र जप, पूजा और साधना से साधक अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है और देवी शक्ति के साथ अपनी आत्मा का संबंध मजबूत करता है। इस प्रकार गुप्त नवरात्र साधक के लिए जीवन बदलने वाला और दिव्यता से भरपूर अवसर साबित होता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

गणतंत्र दिवस परेड को आसान बनाएगी नई व्यवस्था, मेट्रो घोषणाओं से मिलेगा रास्ता और क्यूआर कोड बताएगा पार्किंग

(जीएनएस)। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हर वर्ष की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह भव्य रूप में आयोजित होने जा रहा है, लेकिन इस बार दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। राजधानी में लाखों लोगों की आवाजाही और सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन ने मेट्रो सेवाओं, पार्किंग प्रबंधन और मार्गदर्शन प्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं ताकि परेड देखने आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष मेट्रो स्टेशनों पर विशेष प्रकार की घोषणाएं की जाएंगी, जिनके माध्यम से टिकट और पास धारकों को सीधे उनके बैठने वाले एंक्लोज़र तक पहुंचने का सटीक मार्ग बताया जाएगा। दिल्ली मेट्रो को इस पूरे आयोजन की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक दर्शक मेट्रो के माध्यम से ही कर्तव्य पथ तक पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मेट्रो स्टेशनों पर ऐसी ऑडियो घोषणाएं तैयार की गई हैं, जो यात्रियों को यह स्पष्ट जानकारी देंगी कि उन्हें किस स्टेशन पर उतरना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। हर दर्शक के पास पर एंक्लोज़र का नाम अंकित होगा और उसी के आधार पर उन्हें उत्तर या दक्षिण हिस्से की ओर जाने का निर्देश दिया जाएगा। इससे पहले कई बार लोग सही मार्ग न समझ पाने के कारण भटक जाते थे, लेकिन इस बार व्यवस्था को पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

इस वर्ष एक खास बदलाव यह किया गया है कि सभी दर्शक दीर्घाओं यानी एंक्लोज़र के नाम भारत की प्रमुख नदियों के नाम पर रखे गए हैं। इसका उद्देश्य न केवल भारतीय सांस्कृतिक पहचान को दर्शाना है, बल्कि लोगों के लिए पहचान को आसान बनाना भी है। कर्तव्य पथ के दक्षिणी हिस्से में ब्यास, ब्रह्मपुत्र, चंबल, चेनाब, गंडक, गंगा, घाघरा, गोदावरी, सिंधु और झेलम नाम के एंक्लोज़र बनाए गए हैं, जिनमें बैठने वाले दर्शकों को उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर उतरने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तरी हिस्से में कावेरी, कोसी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, पेन्नार, पेरियार, रवि, सोन, सतलुज, तीस्ता, वैगई और यमुना एंक्लोज़र निर्धारित किए गए हैं, जिनके लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन सबसे उपयुक्त रहेगा। मेट्रो से बाहर निकलते ही दिशा सूचक बोर्ड और स्वयंसेवक भी लोगों का मार्गदर्शन करेंगे।

वाहनों से आने वाले दर्शकों के लिए इस बार क्यूआर कोड आधारित पार्किंग प्रणाली लागू की गई है, जिसे एक आधुनिक और स्मार्ट कदम माना जा रहा है। पहले लोग पार्किंग स्थल खोजने में काफी समय गंवा देते थे और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती थी। अब प्रत्येक पार्किंग पास पर एक विशेष क्यूआर कोड अंकित होगा, जिसे मोबाइल से स्कैन करते ही दर्शकों को उनके लिए निर्धारित पार्किंग स्थल का रीयल टाइम रास्ता दिखाई देगा। राजधानी के विभिन्न हिस्सों में कुल 22 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, जहां लगभग 8,000 वाहनों को खड़ा करने की क्षमता रखी गई है। पार्किंग स्थल से कर्तव्य पथ तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग भी तय किए गए हैं, ताकि भीड़ एक साथ जमा न हो।

दिल्ली पुलिस और यातायात विभाग का कहना है कि हर वर्ष लगभग 77 हजार पास गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जारी किए जाते हैं, जिनमें से करीब 8 हजार पास वाहन से आने वाले दर्शकों के लिए होते हैं। इतनी बड़ी संख्या को नियंत्रित करना आसान नहीं होता, इसलिए इस बार तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। क्यूआर कोड और मेट्रो घोषणाओं की संयुक्त व्यवस्था से न केवल भ्रम कम होगा, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भीड़ प्रबंधन में भी बड़ी मदद मिलेगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे अनावश्यक भीड़भाड़, गलत दिशा में जाने की समस्या और ट्रैफिक अव्यवस्था पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा।

प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे निजी वाहनों की बजाय अधिक से अधिक मेट्रो का उपयोग करें, समय से पहले घर से निकलें और अपने पास पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। मेट्रो स्टेशनों, पार्किंग स्थलों और कर्तव्य पथ के आसपास बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, जो लोगों की सहायता करेंगे। गणतंत्र दिवस देश की एकता और गौरव का पर्व है और इसे देखने के लिए आने वाला हर नागरिक सम्मान का पात्र है। नई व्यवस्थाओं का उद्देश्य यही है कि लोग बिना किसी तनाव के परेड का आनंद ले सकें और राजधानी में यह राष्ट्रीय उत्सव पूरी गरिमा और अनुशासन के साथ संपन्न हो सके।

तेजस्वी यादव की 'ताजपोशी' की तैयारी आरजेडी में बड़े संगठनात्मक बदलाव के संकेत

(जीएनएस)। पटना। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखे जाने की तैयारी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल में लंबे समय से जिस पीढ़ीगत बदलाव की चर्चा चल रही थी, वह अब जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। 25 जनवरी को बुलाई गई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। राजनीतिक गलियारों में इसे आरजेडी के भविष्य की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व सांसद और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि इसी मंच से तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की घोषणा की जाएगी। यह कदम केवल पद परिवर्तन नहीं, बल्कि पार्टी की पूरी कार्यशैली और नेतृत्व संरचना में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है।

लालू प्रसाद यादव के दौर की राजनीति से निकलकर आरजेडी अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है।

विदेश दौरे से लौटने के बाद तेजस्वी यादव की सक्रियता अचानक काफी बढ़ गई है।

उन्होंने लगातार संगठन के नेताओं के साथ बैठकें की हैं, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है और पार्टी की आगे की रणनीति पर मंथन किया है। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए आरजेडी अपने संगठन को नए सिरे से खड़ा करना चाहती है, जिसमें युवा नेतृत्व को केंद्र में रखा जाएगा। तेजस्वी यादव पहले से ही चुनावी अभियानों का चेहरा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें संगठन की कमान भी औपचारिक रूप से सौंपने की तैयारी है।

लालू प्रसाद यादव की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के कारण पार्टी के अंदर यह महसूस किया जा रहा था कि नेतृत्व का बोझ पूरी तरह तेजस्वी के कंधों पर आना चाहिए। हालांकि व्यावहारिक रूप से वह लंबे समय से पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता बने हुए हैं, लेकिन अब तक औपचारिक रूप से सर्वोच्च पद पर उनकी ताजपोशी नहीं हुई थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में यह बदलाव जरूरी हो गया है, ताकि कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच स्पष्ट संदेश जा सके कि आरजेडी का भविष्य तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला केवल संगठनात्मक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी अहम होगा। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन के मुकाबले आरजेडी को एक मजबूत और स्थायी नेतृत्व की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने पिछले चुनावों में अपनी लोकप्रियता साबित की है और युवाओं के बीच उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई है। ऐसे में पार्टी उन्हें औपचारिक रूप से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक स्पष्ट नेतृत्व मॉडल पेश करना चाहती है। आरजेडी के भीतर इस बदलाव को लेकर उत्साह का माहौल है। कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव की कार्यशैली लालू प्रसाद यादव से अलग जरूर है, लेकिन वह जमीनी राजनीति को उतनी ही मजबूती से समझते हैं। सामाजिक न्याय, रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर उनकी आक्रामक राजनीति ने पार्टी को नया आधार दिया है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा तथा चुनावी लड़ाइयों में आरजेडी अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेगी।

हालांकि इस संभावित ताजपोशी को लेकर औपचारिक घोषणा 25 जनवरी की बैठक के बाद ही होगी, लेकिन जिस तरह से पार्टी के अंदरूनी संकेत मिल रहे हैं, उससे साफ है कि यह महज औपचारिकता भर रह गई है। बिहार की राजनीति में यह बदलाव आने वाले दिनों में सत्ता समीकरणों पर भी असर डाल सकता है। तेजस्वी यादव के हाथों में संगठन की बागडोर आने के बाद आरजेडी किस दिशा में आगे बढ़ेगी, यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि यह फैसला बिहार की सियासत में नई हलचल जरूर पैदा करेगा।

'शंकराचार्य जीवित आध्यात्मिक गुरु अपमान हिंदुओं के लिए शर्मिंदगी': AAP नेता ने यूपी सरकार पर बोला हमला

(जीएनएस)। प्रयागराज। माघ मेला क्षेत्र में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वानंद सरस्वती के साथ हुई कथित अभद्रता का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस घटना को हिंदू समाज के लिए बेहद अपमानजनक बताते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जैसे सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु के साथ इस तरह का व्यवहार पूरे सनातन समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है और यह दिखाता है कि मौजूदा सरकार के दौर में धर्म की असली परंपराओं को हाशिये पर धकेला जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर माघ मेले के दौरान हुई घटना का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि शंकराचार्य केवल कोई साधारण संत नहीं, बल्कि जीवित आध्यात्मिक परंपरा के सबसे बड़े स्तंभ हैं। वे वैदिक ज्ञान, शास्त्रीय परंपराओं और सनातन संस्कृति के संरक्षक हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार प्रमुख मठों की विरासत आज भी उन्हीं के माध्यम से जीवित है। ऐसे में उनके साथ अपमानजनक व्यवहार होना केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि पूरी धार्मिक परंपरा का अपमान है।

आप नेता ने अपने बयान में कहा कि पहले हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व शंकराचार्य, धर्माचार्य और विद्वान संत किया करते थे, जो समाज को संयम, करुणा और ज्ञान का रास्ता दिखाते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक नई छवि गढ़ी गई है, जिसमें हिंसा करने वाले कांवड़ियों और उग्र भीड़ को सनातन का चेहरा बना दिया गया है। यह बदलाव स्वाभाविक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य धर्म के मूल स्वरूप को विकृत करना है।

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि योगी सरकार के शासन में पिछले दस वर्षों में धार्मिक आयोजनों का चरित्र पूरी तरह बदल गया है। आध्यात्मिक विमर्श की जगह प्रदर्शनकारी धार्मिकता ने ले ली है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जैसे संत जब सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं या परंपराओं के अनुसार अपना मत रखते हैं तो उन्हें सम्मान देने के बजाय अपमानित किया जाता है। यह प्रवृत्ति बेहद खतरनाक है और भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे।

इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी वाराणसी में मंदिरों को तोड़े जाने के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि काशी जैसे पवित्र नगर में प्राचीन मंदिरों और धरोहरों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन सरकार मौन है। अब प्रयागराज की इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भाजपा सरकार वास्तव में धर्म की संरक्षक है या केवल राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी इस प्रकरण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के काफिले को रोका जाना और उनके साथ अनुचित व्यवहार करना निंदनीय है। सरकार को तत्काल इस मामले में माफी मांगनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अजय राय ने यह भी कहा कि जो सरकार खुद को हिंदुत्व की सबसे बड़ी पैरोकार बताती है, वही धर्माचार्यों का अपमान कर रही है, यह दोहरा चरित्र जनता के सामने उजागर हो चुका है।

माघ मेला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां देशभर के संत-महात्मा एकत्र होते हैं। ऐसे आयोजन में शंकराचार्य जैसे सर्वोच्च धर्मगुरु के साथ हुआ व्यवहार न केवल प्रशासनिक विफलता है, बल्कि धार्मिक संवेदनाओं पर सीधा आघात है। साधु-संत समाज के कई प्रतिनिधियों ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई है और कहा है कि अगर शंकराचार्यों का ही सम्मान सुरक्षित नहीं है तो सामान्य श्रद्धालुओं की क्या स्थिति होगी।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विवाद आने वाले दिनों में और गहराएगा। विपक्ष इस मुद्दे को हिंदू अस्मिता और धार्मिक परंपराओं से जोड़कर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस सफाई सामने नहीं आई है, जिससे असंतोष बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज की इस घटना ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि सनातन परंपरा की असली आवाज कौन है—शास्त्रों के ज्ञाता शंकराचार्य या राजनीतिक मंचों से गढ़ी गई नई धार्मिक पहचान।

ट्रंप को नोबेल 'गिफ्ट' करने के दावे पर फाउंडेशन ने दी दो टूक, कहा—'पुरस्कार ट्रांसफर नहीं हो सकता'

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार 'गिफ्ट' करने के दावे ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी। इस दावे के तुरंत बाद नोबेल फाउंडेशन ने स्पष्ट कर दिया कि नोबेल पुरस्कार न तो किसी और के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है और न ही किसी को प्रतीकात्मक रूप से सौंपा जा सकता है।

मचाडो ने 15 जनवरी को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान कहा था कि वह अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को समर्पित करना चाहती हैं। इस बयान के बाद मीडिया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में बहस शुरू हो गई, जिससे फाउंडेशन को इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देनी पड़ी।

नोबेल फाउंडेशन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उनका प्रमुख दायित्व अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत और पुरस्कार की गरिमा को बनाए रखना है। वसीयत के अनुसार, नोबेल पुरस्कार केवल उसी व्यक्ति को

दिया जा सकता है जिसने मानवता के लिए असाधारण योगदान किया हो। एक बार विजेता घोषित होने के बाद पुरस्कार को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना या किसी और के नाम करना पूरी तरह से असंभव है। फाउंडेशन ने यह भी स्पष्ट किया कि पुरस्कार देने का अधिकार अलग-अलग नोबेल समितियों के पास होता है और इसमें किसी तरह का निजी हस्तांतरण या राजनीतिक निर्णय मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि भले ही विजेता अपने मेडल या डिप्लोमा को किसी के पास रख दें, लेकिन इतिहास में नोबेल विजेता वही रहेगा जिसे आधिकारिक रूप से पुरस्कार मिला है।

नोबेल शांति पुरस्कार में विजेता को सोने का मेडल, आधिकारिक डिप्लोमा और पुरस्कार राशि दी जाती है। फाउंडेशन ने यह भी स्पष्ट किया कि विजेता अपने पुरस्कार को किसी और के साथ साझा नहीं कर सकता और न ही उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि, फाउंडेशन विजेताओं की राजनीतिक गतिविधियों या निजी फैसलों पर कोई टिप्पणी नहीं करता।

विशेषज्ञों का मानना है कि मचाडो के इस कदम ने नोबेल फाउंडेशन की सख्ती और नियमों की आवश्यकता को फिर से उजागर किया है। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दिया कि नोबेल पुरस्कार केवल मूल नियमों और विजेता की योग्यता पर आधारित है, और इसे किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत कारण से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

'बंगाल बदलाव के लिए तैयार': पीएम मोदी की रैली ने सियासत में नया ताप पैदा किया

(जीएनएस)। सिंगूर/कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस समय बदलाव की हवा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगूर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल अब बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीते 24 घंटे में जितने बड़े विकास कार्य हुए हैं, वह पिछले 100 वर्षों में शायद ही कभी हुए हों। पीएम मोदी ने पूर्वी भारत को विकसित भारत की नींव करार दिया और केंद्र सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं को ऐतिहासिक बताया। रैली में पीएम मोदी ने मालदा और हुगली जैसे जिलों के विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल अब देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से जुड़ा है, और राज्य को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं। इनमें दिल्ली, तमिलनाडु और काशी को जोड़ने वाली तीन नई ट्रेनें शामिल हैं, जो राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। प्रधानमंत्री ने बालागढ़ में बनने वाले एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम का भी उल्लेख किया और कहा कि इससे हुगली क्षेत्र में कारोबार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

गंगा जलमार्ग के विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि इससे कार्गो मूवमेंट में तेजी आएगी, उद्योगों को सस्ती और तेज परिवहन सुविधा मिलेगी और कोलकाता पर ट्रैफिक व लॉजिस्टिक दबाव कम होगा। पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार लगातार बंगाल के विकास के लिए काम कर रही है, और आने वाले समय में इसका असर हर क्षेत्र में दिखाई देगा। रैली में पीएम मोदी ने कानून-व्यवस्था और घुसपैठ के मुद्दों को लेकर भी राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। पीएम ने कहा कि अवैध प्रवासी गरीबों का हक छीन रहे हैं और फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस उनके देश भेजना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में नौजवानों और महिलाओं की सुरक्षा के मामलों में टीएमसी सरकार असफल रही है। प्रधानमंत्री के बयान पर टीएमसी ने तुरंत पलटवार किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जॉय प्रकाश मजूमदार ने कहा कि घुसपैठ के आरोप निराधार हैं और कोई ठोस सबूत नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में 58 लाख नाम हटाए गए, लेकिन एक भी मामला घुसपैठ से संबंधित नहीं पाया गया। टीएमसी ने यह स्पष्ट किया कि न तो बांग्लादेशी नागरिक और न ही रोहिंग्या अवैध रूप से मतदाता सूची में शामिल पाए गए। कानून-व्यवस्था पर पीएम मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए टीएमसी ने NCRB के आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि महिला अपराध और सुरक्षा की स्थिति अन्य राज्यों में कहीं अधिक गंभीर है। साथ ही पार्टी ने केंद्र से सवाल उठाया कि मणिपुर हिंसा, कश्मीर और दिल्ली में आतंकी घटनाओं पर केंद्र सरकार की चुप्पी क्यों है।

विश्लेषकों का कहना है कि पीएम मोदी के विकास और घुसपैठ से जुड़े बयानों ने बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी ताप बढ़ा दिया है। विकास और कानून-व्यवस्था के मुद्दे दोनों ही भाजपा और टीएमसी के बीच मतदाताओं के मन में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। विश्लेषकों के अनुसार, बंगाल की जनता पर यह रैली गहरा प्रभाव डाल सकती है और टीएमसी के लिए चुनौती और बढ़ सकती है।

सियासी मोर्चे पर यह रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पीएम मोदी ने बंगाल में केंद्र सरकार की परियोजनाओं और योजनाओं का व्यापक बखान किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य के विकास के लिए अब तक जितने बड़े कदम उठाए गए हैं, वह पिछले दशकों में कभी नहीं हुए। पीएम मोदी ने कहा कि उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में निवेश-friendly माहौल तैयार किया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। घुसपैठ और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि यह परिवर्तन केवल योजनाओं और परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर जनता के जीवन स्तर पर भी दिखाई देगा।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बंगाल में सियासत अब और अधिक गर्म होने वाली है। विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर पीएम मोदी की रैली ने भाजपा को एक ताकतवर चुनावी संदेश दिया है, जबकि टीएमसी को अपने शासन और विकास एजेंडे को लेकर जवाबी रणनीति बनानी होगी। आने वाले महीनों में दोनों पार्टियों के बीच मतदाता पर प्रभाव डालने की होड़ और तेज होगी, और यह बंगाल की सियासत में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के तीन जवान घायल, ऑपरेशन जारी

(जीएनएस)। जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सुदूर और घने जंगलों में रविवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच भयंकर मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के तीन जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने छतरू के पास सोननार क्षेत्र में खुफिया सूचना के आधार पर संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान आतंकियों ने घात लगाकर सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान इलाके में दो से तीन आतंकियों के फंसे होने की आशंका है।

छतरू और सोननार क्षेत्र के जंगल बेहद घने और कठिन भूगोल वाले हैं, इसलिए ऑपरेशन बेहद सतर्कता और योजना के साथ चलाया जा रहा है। सेना और पुलिस ने इलाके की पूरी घेराबंदी कर दी है और आतंकियों को अलग-अलग दिशा में भागने से रोकने के लिए अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन को और प्रभावी बनाने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। मुठभेड़ में घायल तीन जवानों को गोली के छर्रों के चलते तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि उनकी स्थिति स्थिर है और उन्हें विशेषज्ञ इलाज मिल रहा है। सेना का मानना है कि घायल जवान जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे, जबकि ऑपरेशन जारी रहने के कारण आतंकियों को घेरने और निष्क्रिय करने की कवायद तेज की जा रही है।

इस साल जम्मू क्षेत्र में किश्तवाड़ मुठभेड़ तीसरी मानी जा रही है। इससे पहले कठुआ जिले के बिलवार क्षेत्र के कहोग और नजोते जंगलों में 7 और 13 जनवरी को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने इन मुठभेड़ों में कई आतंकियों को निशस्त्र करने और इलाके में तनाव नियंत्रण में रखने में सफलता हासिल की थी।

किश्तवाड़ मुठभेड़ के चलते पूरे इलाके में तनाव है। सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन मिलकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं और आम जनता को जंगलों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल पूरी सावधानी के साथ आतंकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

गाजा बोर्ड ऑफ पीस में भारत को न्योता, पीएम मोदी को ट्रंप ने आमंत्रित किया

(जीएनएस)। नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय संगठन 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने का आमंत्रण भेजा है। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य गाजा में स्थायी शांति स्थापित करना, युद्ध से तबाह बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना और मानवीय सहायता को सुनिश्चित करना है। बोर्ड के गठन की घोषणा 15 जनवरी को ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली शांति योजना के दूसरे चरण के तहत की गई थी।

बोर्ड का निर्माण विशेष रूप से गाजा को हथियारों से मुक्त करने, मानवीय सहायता सुनिश्चित करने और नए प्रशासनिक ढांचे की स्थापना करने पर केंद्रित है। इस प्रक्रिया के तहत गाजा में एक तकनीकी फिलिस्तीनी प्रशासन स्थापित किया जाएगा, जिसका संचालन नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा (NCAG) करेगी। इस समिति के नेतृत्व में पूर्व फिलिस्तीनी अधिकारी अली शाथ रहेंगे, जो प्रशासनिक और नीतिगत निर्णयों की निगरानी करेंगे।

डोनाल्ड ट्रंप ने इस बोर्ड को अब तक का सबसे महान और प्रतिष्ठित बोर्ड करार दिया। उन्होंने कहा कि यह न केवल शांति स्थापना बल्कि गाजा के विकास और स्थिरता के लिए ऐतिहासिक प्रयास है। बोर्ड की फाउंडर एग्जीक्यूटिव कमेटी में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ट्रंप के दामाद और प्रमुख सलाहकार जेरेड कुशनर, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष अजय बंगा, व्यवसायी मार्क रोवन और सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल शामिल हैं।

अमेरिकी दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि आने वाले हफ्तों में एग्जीक्यूटिव बोर्ड और गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अन्य सदस्यों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के मिडिल ईस्ट के पूर्व दूत निकोलाय म्लादेनोव को गाजा के लिए हाई रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है।

गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसमें तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान, यूएई की मंत्री रीम अल-हाशिमी और कतर के राजनयिक अली अल-थावादी शामिल हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिकी नेतृत्व के साथ अरब देशों की भागीदारी भी इस बोर्ड के कामकाज में निर्णायक भूमिका निभाएगी। इसके अलावा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी को भी इस बोर्ड में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। पाकिस्तान ने भी पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बोर्ड में शामिल होने का आमंत्रण मिला है।

विशेषज्ञों का मानना है कि गाजा बोर्ड ऑफ पीस एक वैश्विक पहल के रूप में मध्यपूर्व में स्थायी शांति और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। आने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस बोर्ड के कामकाज और सदस्य देशों की भागीदारी पर भी विशेष चर्चा होने की संभावना है। यह बोर्ड केवल एक प्रशासनिक निकाय नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक बनकर उभर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना इस पहल को और मजबूती दे सकती है। भारत की भागीदारी न केवल मध्यपूर्व में शांति प्रयासों में योगदान को दर्शाएगी, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीतिक स्थिति को भी मजबूत करेगी। गाजा बोर्ड ऑफ पीस के जरिए मानवीय सहायता, आर्थिक पुनर्निर्माण और स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयासों को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी-2024 के अंतर्गत अहम निर्णय

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने टेक्सटाइल पॉलिसी-2024 के तहत पहली बार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण एवं उनकी आय में वृद्धि का दृष्टिकोण अपनाया है।

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के इस दृष्टिकोण को अधिक व्यापक बनाने के लिए टेक्सटाइल पॉलिसी के कुछ प्रावधानों में महत्वपूर्ण सुधार करने के निर्देश दिए हैं।

तदनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में पंजीकृत या अन्य ऐसे स्वैच्छिक स्वयं सहायता समूह, जिसमें आजीविका के समान उद्देश्य से जुड़ीं महिलाओं के एक या एक से अधिक स्वयं सहायता समूह शामिल हैं, को टेक्सटाइल पॉलिसी के अंतर्गत लाभ मिल पाएगा।

मुख्यमंत्री ने एक अन्य निर्णय यह भी किया है कि राज्य में म्युनिसिपल क्षेत्र की सीमा के अंदर स्थित गारमेंट, अपैरल और मेडअप्स, स्टिचिंग, एंब्रॉयडरी तथा अन्य गतिविधियों से जुड़ी गैर-प्रदूषणकारी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों वाली इकाइयों को भी इस टेक्सटाइल पॉलिसी-2024 का लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल पॉलिसी-2024 के अंतर्गत राज्य की अर्थव्यवस्था और देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कपड़ा उद्योग की टेक्सटाइल वैल्यू चेन के हरेक सेगमेंट का विश्लेषण करके गारमेंट और अपैरल तथा टेक्निकल टेक्सटाइल पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की रणनीति अपनाई है।

इसके अंतर्गत, गारमेंट, अपैरल और मेडअप्स, स्टिचिंग तथा एंब्रॉयडरी जैसी गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों के अलावा अन्य मूल्य वर्धित गतिविधियों वाली इकाइयां, जो गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) की मौजूदा वाइट कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी या उसके समकक्ष जीपीसीबी के वर्तमान प्रावधान/कैटेगरी क्लासिफिकेशन के तहत शामिल हैं, साथ ही जो महानगर पालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थापित हैं, उन्हें भी गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी-2024 के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र माना जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस निर्णय से राज्य के महानगर पालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित गैर-प्रदूषणकारी टेक्सटाइल इकाइयों को योजना का काफी लाभ मिलेगा।

इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा तथा कुशल एवं अर्धकुशल कामगारों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

गैर-प्रदूषणकारी टेक्सटाइल गतिविधियों को शहरी क्षेत्र में मान्यता मिलने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास के लिए भी अनुकूल वातावरण मिलेगा।

इसके अलावा, मनपा क्षेत्र में उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का प्रभावी उपयोग होगा, जिससे उत्पादन लागत में कमी आएगी और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन मिलेगा।

शहरी क्षेत्रों में गारमेंट, अपैरल, स्टिचिंग और एंब्रॉयडरी जैसी लेबर-इंटेंसिव (बड़े पैमाने पर श्रम की खपत) तथा गैर-प्रदूषणकारी टेक्सटाइल गतिविधियां होने से महिला कर्मचारियों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी और वर्क-लाइफ बैलेंस यानी कार्य-जीवन संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने से पर्यावरण सुरक्षा तथा संतुलित एवं टिकाऊ औद्योगिक विकास के उद्देश्य भी पूरे हो सकेंगे।

गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी-2024 के अंतर्गत पात्र स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त मुख्यमंत्री के इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य की महिलाएं आर्थिक रूप से और भी सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

इस प्रकार के कदम उन्हें अधिक अवसर और सशक्तता प्रदान करेंगे, ताकि वे समाज, अर्थव्यवस्था और व्यवसाय के क्षेत्र में और भी मजबूत बन सकें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री सह उद्योग मंत्री श्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी-2024 में किए गए इन सुधारों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर भी पूरक बनेगा और गुजरात 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी योगदान दे सकेगा।

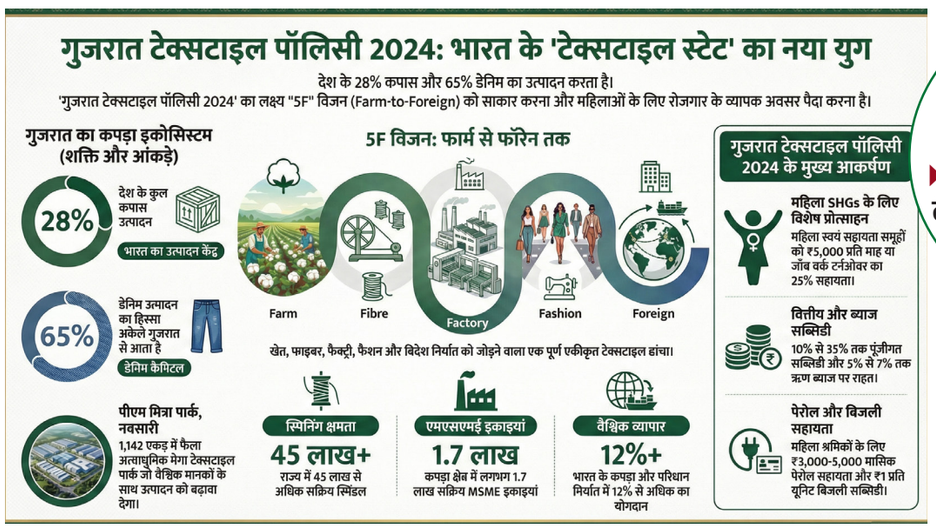

महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को अधिक व्यापक बनाया जाएगा

मनपा क्षेत्र में स्थित गैर-प्रदूषणकारी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों वाली इकाइयों को मिलेगा पॉलिसी का लाभ

पालनपुर-सामाखियाली खंड पर रेल परिचालन बहाल

(जीएनएस)। अहमदाबाद मंडल के पालनपुर–सामाखियाली खंड पर किडियानगर स्टेशन (सामाखियाली से चौथा स्टेशन) पर दिनांक 18.01.2026 को प्रातः 02:25 बजे डाउन लाइन में जा रही मालगाड़ी संख्या STPP/MDCC (लोको संख्या 49384) के दो वैगनों के पटरी से उतर जाने के कारण अप एवं डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ था। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।

प्रातः 08:05 बजे अप एवं डाउन दोनों लाइनों पर सामान्य रेल परिचालन पुनः बहाल कर दिया गया है।

इस दौरान निम्नलिखित गाड़ियाँ प्रभावित रहीं:

गाड़ी संख्या 19406/19405 गांधीधाम–पालनपुर–गांधीधाम एक्सप्रेस पूर्णतः रद्द रही।

गाड़ी संख्या 12959 बांद्रा टर्मिनस–भुज एक्सप्रेस को भिलडी–मेहसाणा–विरमगाम–सामाखियाली मार्ग से परिवर्तित मार्ग से चलाया गया।

गाड़ी संख्या 20984 दिल्ली सराय रोहिल्ला–भुज एक्सप्रेस को भी भिलडी–मेहसाणा–विरमगाम–सामाखियाली मार्ग से परिवर्तित मार्ग से चलाया गया।

गाड़ी संख्या 22483 भगत की कोठी–गांधीधाम एक्सप्रेस को भिलडी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया।

घटना की सूचना मिलते ही राहत ट्रेन मौके पर रवाना हो गई तथा मण्डल रेल प्रबंधक अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुँच गए।

ईरान संकट में फंसा बासमती चावल का कारोबार, निर्यातकों की मुश्किलें बढ़ीं

(जीएनएस)। नई दिल्ली। ईरान में चल रहे राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के हालात का असर अब सीधे भारत के व्यापारिक हितों पर देखने को मिल रहा है। बासमती चावल के प्रमुख निर्यातक देश के लिए ईरान हमेशा एक महत्वपूर्ण बाजार रहा है, लेकिन मौजूदा संकट ने इस रणनीतिक व्यापार को संकट में डाल दिया है। भारतीय निर्यातकों के सामने न केवल नए ऑर्डर ठप्प हुए हैं, बल्कि पहले भेजे गए चावल के कंसाइनमेंट का भुगतान भी लंबित है, जिससे व्यापारियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। भारतीय चावल निर्यातक महासंघ (आईआरईएफ) के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से नवंबर के बीच भारत ने ईरान को लगभग 5.98 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया था। लेकिन हाल ही में ईरान में विरोध-प्रदर्शन और

राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां की आर्थिक गतिविधियां ठप्प हो गई हैं। आईआरईएफ के अध्यक्ष प्रेम गर्ग के अनुसार, तेहरान समेत कई प्रमुख शहरों में बाजार बंद हैं और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी के कारण ईरानी आयातकों से संपर्क टूट गया है। इसके परिणामस्वरूप कई कंसाइनमेंट ईरानी बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं, और उनके भुगतान की प्रक्रिया अनिश्चितता की स्थिति में है। ईरान भारत के लिए बासमती चावल का अमेरिका से भी बड़ा खरीदार माना जाता है। यह तथ्य इस संकट को और गंभीर बनाता है, क्योंकि नए निर्यात ऑर्डर न मिलने से निर्यातकों की आय पर सीधा असर पड़ रहा है। इसके अलावा, अमेरिका की नीति के तहत ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त शुल्क और प्रतिबंधों का खतरा भी बना हुआ है, जिससे निर्यातक और भी सतर्क हो गए हैं। हालांकि, संकट का असर केवल निर्यात और भुगतान पर ही नहीं है, बल्कि घरेलू बाजारों पर भी दिखने लगा है। आईआरईएफ के अनुसार, बीते सप्ताह बासमती चावल की प्रमुख किस्मों के दामों में औसतन सात प्रतिशत की गिरावट आई है। उदाहरण के लिए, 1121 किस्म जहां 85 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, वह अब 80 रुपये प्रति किलो पर आ गई है, वहीं 1121 सेला किस्म 75 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। अन्य किस्मों—1509, 1718 और 1401—में भी पांच से सात रुपये प्रति किलो तक की कमी दर्ज की गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की मुद्रा रियाल के डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने और देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों ने वहां की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया है। इसका सीधा असर भारत-ईरान व्यापार पर भी पड़ा है और फिलहाल यह स्थिति बनाए रखने की संभावना जताई जा रही है। निर्यातक चिंतित हैं कि अगर ईरान में हालात जल्द सामान्य नहीं हुए, तो न केवल मौजूदा भुगतान लंबित रह सकते हैं, बल्कि आने वाले महीनों में नए ऑर्डर भी प्रभावित हो सकते हैं।

इसके अलावा, इस संकट का एक अप्रत्यक्ष असर भारतीय किसानों और थोक बाजारों पर भी पड़ा है। चावल की कीमतों में गिरावट से किसानों की आमदनी प्रभावित होने लगी है और घरेलू थोक बाजारों में मांग और आपूर्ति के संतुलन पर अस्थिरता देखने को मिल रही है। इससे बासमती चावल की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और भारत की निर्यात संभावनाओं पर भी दबाव पड़ सकता है।

आईआरईएफ का कहना है कि सरकार और निर्यातक मिलकर स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि निर्यातकों को भुगतान जोखिम को कम करने के लिए अग्रिम भुगतान या बैंक गारंटी जैसी सावधानियां अपनानी चाहिए। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान में हालात जल्द सामान्य होते हैं, तो भारत का बासमती चावल व्यापार फिर से पटरी पर लौट सकता है।

फिलहाल, ईरान में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के कारण भारत का बासमती निर्यात संकट में फंसा हुआ है। यह स्थिति निर्यातकों, किसानों और घरेलू थोक बाजारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, और आने वाले महीनों में इसका असर पूरी बासमती आपूर्ति श्रृंखला पर देखने को मिल सकता है।

टाटा मुंबई मैराथन 2026 में मुंबई के साथ दौड़ी पश्चिम रेलवे

'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में : 150 सदस्यीय पश्चिम रेलवे टीम ने फिटनेस, रेल सेफ्टी एवं नागरिक कर्तव्यों का दिया संदेश

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे ने आज मुंबई में आयोजित टाटा मुंबई मैराथन 2026 में सहभागिता कर उत्साहपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई तथा फिटनेस, अनुशासन और सुरक्षा जागरूकता का सशक्त संदेश दिया। पश्चिम रेलवे के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से युक्त 150 सदस्यीय टीम ने 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के सम्मान एवं उत्सव के रूप में इस मैराथन में भाग लिया। यह सहभागिता राष्ट्रीय गौरव, सामूहिक अनुशासन तथा दैनिक जीवन में स्वस्थ जीवनशैली के महत्व का प्रतीक रही।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने पश्चिम रेलवे की टीम का नेतृत्व किया। इस दौरान कई वरिष्ठ रेल अधिकारियों ने भी मैराथन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे फिटनेस, संरक्षा तथा जनसंपर्क के प्रति नेतृत्व की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई। इस टीम में स्टेशन मास्टर, टिकट जांच कर्मचारी, ट्रेन प्रबंधक, कोचिंग डिपो कर्मचारी तथा ट्रैकमैन जैसी प्रमुख फ्रंटलाइन एवं परिचालन श्रेणियों के कर्मचारी शामिल थे, जिन्होंने आधिकारिक यूनिफॉर्म में भाग लेकर आम जनता को सशक्त सामाजिक एवं सुरक्षा

संदेश दिया। टीम ने रचनात्मक ब्रांडिंग एवं जनसंपर्क सामग्री के माध्यम से प्रभावशाली जागरूकता संदेश प्रदर्शित किए, जिनमें "रेल सुरक्षा के लिए दौड़", "पटरियों का सम्मान करें", "पटरी से दूर रहें – सुरक्षित रहें" जैसे नारे प्रमुख रूप से शामिल थे। इसके साथ ही "मुंबई की लाइफलाइन", "पश्चिम रेलवे परवाह करता है" तथा "मुंबई दौड़ती है क्योंकि हम दौड़ते हैं" जैसे पश्चिम रेलवे के ब्रांड संदेश भी प्रदर्शित किए गए। इस सहभागिता की एक विशिष्ट विशेषता यह रही कि टीम के 50 सदस्यों ने अपनी आधिकारिक युनिफार्म वर्दी में दौड़ लगाई, जिससे यह सशक्त संदेश गया कि शारीरिक फिटनेस व्यावसायिक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत कल्याण का अभिन्न अंग है। यह प्रतीकात्मक सहभागिता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित फिट इंडिया मूवमेंट की भावना के अनुरूप रही तथा इस संदेश को और अधिक सुदृढ़ किया कि शारीरिक तंदुरुस्ती को सभी व्यवसायों और आयु वर्गों में दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

पश्चिम रेलवे की यह सहभागिता केवल एक दौड़ तक सीमित न होकर कहीं अधिक व्यापक महत्व की रही। इससे संगठन की इस सोच को बल मिला कि शारीरिक फिटनेस जीवन की परिस्थितियों या पेशे से परे हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है तथा एक स्वस्थ कार्यबल ही सुरक्षित, अधिक दक्ष और विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुशासित एवं वर्दीधारी टीम की सशक्त उपस्थिति ने जनसंपर्क को भी सुदृढ़ किया तथा सुरक्षा के प्रति जागरूकता और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार के महत्व को और अधिक प्रभावी ढंग से रेखांकित किया।

मैराथन के इस मंच का उपयोग पश्चिम रेलवे की ब्रांडिंग एवं सुरक्षा जागरूकता को और अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए भी किया गया। इसके अंतर्गत बैनर, प्लाकार्ड, हैंड पोस्टर, इत्यादि पर आधारित दृश्य तत्वों के माध्यम से संदेश प्रसारित किए गए। इसके साथ ही सुव्यवस्थित सोशल मीडिया प्रचार का सहारा लेकर इस अभियान की पहुंच को आयोजन स्थल से आगे बढ़ाकर व्यापक जनसमुदाय तक विस्तार दिया गया।

पश्चिम रेलवे इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करती है, जिन्होंने गर्व और उद्देश्यपूर्ण भावना के साथ संगठन का प्रतिनिधित्व किया। पश्चिम रेलवे रेल सेफ्टी, जन-जागरूकता, फिटनेस तथा राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु निरंतर एवं सार्थक जनसंपर्क पहलों के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराती है।

विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती, सोने की हिस्सेदारी बढ़ने से भारत का बाहरी मोर्चा मजबूत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर मजबूती के संकेत दे रहा है। 9 जनवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 39 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई, जिससे कुल भंडार लगभग 687 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इससे पहले पिछले सप्ताह भंडार में गिरावट देखी गई थी, लेकिन इस बार सोने के भंडार में हुई उल्लेखनीय बढ़ोतरी ने कुल भंडार को सहारा दिया।

विशेष रूप से, विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (Foreign Currency Assets - FCA) में होता है, जिसका स्तर लगभग 550 अरब डॉलर है। हालांकि, इस दौरान FCA में 1.12 अरब डॉलर की मामूली गिरावट दर्ज की गई, लेकिन सोने के भंडार में 1.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप सोने का कुल भंडार अब 112.83 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस वृद्धि ने भारत के बाहरी मोर्चे को और अधिक मजबूती प्रदान की है और इसे वैश्विक आर्थिक अस्थिरताओं के दौरान सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत भी मिली है।

विदेशी मुद्रा भंडार का यह स्तर भारत की आयात जरूरतों को लगभग 11 महीनों तक पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। केंद्रीय बैंक ने दिसंबर में हुई मौद्रिक नीति समीक्षा में भी स्पष्ट किया था कि

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत और लचीली बनी हुई है। इस भंडार का महत्व केवल आयात भुगतान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बाहरी झटकों, जैसे वैश्विक वित्तीय संकट या मुद्रा अस्थिरताओं से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीर्घकालिक रुझानों पर नजर डालें तो वर्ष 2025 में अब तक विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 56 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, जबकि 2024 में यह वृद्धि 20 अरब डॉलर से अधिक रही थी। इसके पहले, 2023 में भंडार में लगभग 58 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था, लेकिन 2022 में यह गिरावट लगभग 71 अरब डॉलर की थी। विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक रणनीतिक रूप से डॉलर की खरीद-फरोख्त करता है और रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाता है। इस दृष्टि से, विदेशी मुद्रा भंडार देश की आर्थिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण संकेतक बन गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की हिस्सेदारी में वृद्धि न केवल भंडार की मात्रा को बढ़ाती है, बल्कि यह निवेशकों और वैश्विक बाजारों के लिए भारत की आर्थिक सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक भी है। यह संकेत देता है कि भारत बाहरी आर्थिक झटकों के खिलाफ अपनी तैयारी में सतर्क और सक्षम है। आने वाले महीनों में यदि वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव जारी रहते हैं, तो भी यह भंडार देश की आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा।

भावनगर मंडल के सीनियर रेलवे इंस्टिट्यूट का उद्घाटन एवं पुनर्विकसित रेलवे स्टेडियम व पार्किंग स्टैंड का लोकार्पण

(जीएनएस)। भावनगर रेलवे मंडल के सीनियर रेलवे इंस्टिट्यूट, भावनगर परा का उद्घाटन दिनांक 18.01.2026 (रविवार) को मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के कर-कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय) श्री मनीष मलिक सहित मंडल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

भावनगर रेलवे मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सीनियर रेलवे इंस्टिट्यूट के नव-निर्मित भवन में रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के लिए खेल एवं मनोरंजन की आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। इंस्टिट्यूट की वार्षिक सदस्यता शुल्क मात्र 25/- निर्धारित किया गया है। सदस्यता प्राप्त करने वाले रेलवे कर्मचारी एवं उनके परिवारजन इनडोर

खेलों जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम तथा आउटडोर खेलों जैसे वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल का लाभ उठा सकेंगे।

कार्यक्रम के दौरान मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए इस प्रकार की सुविधाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर सीनियर रेलवे इंस्टिट्यूट परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। उद्घाटन समारोह में ट्रेड यूनियन के पदाधिकारीगण, बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री शैलेश कुमार परमार, मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक द्वारा किया गया।

इसी दिन, दिनांक 18.01.2026 (रविवार) को मंडल रेल प्रबंधक द्वारा पुनर्विकसित रेलवे स्टेडियम तथा मंडल कार्यालय परिसर में नवनिर्मित पार्किंग स्टैंड का भी लोकार्पण कर इन्हें रेलवे कर्मचारियों को समर्पित किया गया। भावनगर मंडल द्वारा कर्मचारियों के कल्याण एवं बेहतर कार्य परिवेश के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयासों की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है।

जनवरी में विदेशी निवेशकों ने निकाली भारी पूंजी, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने संभाला बाजार का संतुलन

(जीएनएस)। नई दिल्ली। जनवरी महीने की शुरुआत से ही भारतीय शेयर बाजार विदेशी निवेशकों की बिकवाली के दबाव में रहा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इस महीने अब तक लगभग 22,530 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव और अस्थिरता देखने को मिली। यह प्रवृत्ति पिछले साल 2025 में भी जारी रही थी, जब एफपीआई ने पूरे साल के दौरान भारतीय शेयर बाजार से करीब 1.66 लाख करोड़ रुपये की पूंजी बाहर निकाली थी।

फिर भी, विदेशी निवेशकों की इस बिकवाली के बीच घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने बाजार को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनवरी के पहले 16 दिन के दौरान ही डीआईआई ने लगभग 34,076 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की है। बीते वर्ष भी घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी में सक्रिय रहे और उन्होंने कुल लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया। इसने वैश्विक

बाजारों में अस्थिरता के बावजूद भारतीय शेयर बाजार को अपेक्षाकृत स्थिर बनाए रखा और निवेशकों के भरोसे को बनाए रखने में मदद की।

विशेषज्ञों का मानना है कि एफपीआई की बिकवाली के पीछे कई आर्थिक और वैश्विक कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, डॉलर की मजबूती और वैश्विक व्यापार को लेकर अनिश्चितताएं हैं। इसके अलावा, भारत में ऊंची कंपनियों की वैल्यूएशन, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और अमेरिका की संभावित टैरिफ नीतियों को लेकर निवेशकों में आशंकाएं भी बढ़ रही हैं। इन सभी कारकों ने विदेशी निवेशकों को जोखिम कम करने के लिए अपनी पूंजी बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया है। विदेशी पूंजी के बाहर जाने का असर भारतीय रुपये पर भी दिखाई दे रहा है। जनवरी 2026 तक डॉलर के मुकाबले रुपये में लगभग पांच प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई है। यह रुपये की स्थिरता के लिए चुनौतीपूर्ण है, खासकर तब जब वैश्विक आर्थिक माहौल अनिश्चितताओं से भरा हो।

खुराना सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ रवि चंदर खुराना का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर स्पष्टता न होना भी विदेशी निवेशकों के मनोबल को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही, मौजूदा तिमाही के मिश्रित परिणामों ने निवेशकों को सतर्क बना दिया है। उनके अनुसार, जब तक घरेलू बाजार को कोई मजबूत और सकारात्मक संकेत नहीं मिलता, विदेशी निवेशकों की बिकवाली का रुझान जारी रह सकता है।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि घरेलू निवेशकों की सक्रियता ही फिलहाल भारतीय शेयर बाजार को स्थिर बनाए रखने का सबसे बड़ा सहारा है। अगर डीआईआई की खरीदारी कमजोर पड़ती है, तो बाजार पर बिकवाली का दबाव और बढ़ सकता है। इसलिए, निवेशक और विशेषज्ञ दोनों ही बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और आगामी व्यापारिक निर्णयों में वैश्विक और घरेलू संकेतों को प्रमुखता से देख रहे हैं।

हालांकि, वित्तीय विश्लेषक यह भी बताते हैं कि यह प्रवृत्ति अस्थायी हो सकती है। यदि वैश्विक आर्थिक माहौल में सुधार होता है, डॉलर की मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड स्थिर होती है, और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में स्पष्टता आती है, तो विदेशी निवेशकों का बाजार में लौटना संभव है। तब भारतीय शेयर बाजार में नए निवेश और तेजी देखने को मिल सकती है।

इस पूरी परिस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय बाजार अब पूरी तरह वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों से अलग नहीं है। विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और घरेलू संस्थागत निवेशकों की सक्रियता दोनों ही बाजार की दिशा और स्थिरता निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।